

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 102/2020

तारीख रजू 12.10.2020

जाकिर पुत्र बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी जेतपुर।

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार

----- रेस्पोंड

निर्णय

दिनांक 10/8/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 58/2020 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नच्छई के आराजी खसरा नम्बर 161/91, 165/101 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन टीला पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मिर्च की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंड की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्त को बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया जो गलत पारित किया है क्योंकि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर देना चाहिये था जो नहीं दिया गया है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रकरण में अपीलान्त को प्रोपर तामिल नहीं हो पाई है यदि अपीलान्त की प्रोपर तामिल हो जाती तो अपीलान्त अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य सफाई पेश करता जिसका अभाव पाया गया। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 161/91, 165/101 रकबा 2 बीघा भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जो निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर




अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेटाकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त के भाई को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। तथा तामील होने के उपरान्त अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ जिसका प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट पर अपीलान्त के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। तथा चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है यदि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो मवशियों के विचरण करने एवं चारा चरने पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त के घर पर मौजूद नहीं मिलने की स्थिति में तामिल कुन्निदा द्वारा नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चश्पा कर नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्त अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान शामिल मिसल है तथा अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन टीला की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रकृति के मूल स्वरूप को नष्ट करने की चैष्टा की गयी है। मैं वकील पेटाकार की बहस से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक...10/8/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर